सात टेक्सटाइल पार्क बनेंगे 21 लाख लोगों को रोजगार

कैबिनेट फैसले...ढुलाई खर्च घटाने के लिए बनेगा एकीकृत कपड़ा क्षेत्र

नई दिल्ली। कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना के बाद सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पांच साल में सात बड़े एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और टेक्सटाइल पार्क बनाने को मंजूरी दी, जिससे 21 लाख रोजगार मिलेंगे।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पीएम मित्र योजना के तहत 4,445 करोड़ की लागत से बनने वाले सात टेक्सटाइल पार्क के जरिये प्रधानमंत्री के 5एफ विजन की नींव डाली जाएगी। उनकी योजना फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के जरिये भारत को कपड़ा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की है। पीएम मित्र योजना के जरिये देश में विश्व स्तरीय औद्योगिक ढांचे का निर्माण होगा और स्थानीय निवेश के साथ एफडीआई बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। गोयल ने कहा कि निर्माण पूरा होने के बाद हर टेक्सटाइल पार्क एक लाख प्रत्यक्ष और दो लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। एक पार्क में 1700 करोड़ की लागत आएगी, जो एक हजार एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। गोयल ने बताया कि कपड़ा क्षेत्र के लिए यह सातवीं घोषणा है। इससे पहले 10,683 करोड़ की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के जरिये भी पांच साल में तीन लाख करोड़ का टर्नओवर बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो

4,445 करोड़ खर्च किए जाएंगे पांच साल में, सात लाख प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा

उत्पादन खर्च में होगी कमी 10 राज्यों ने दिखाई रुचि

एकीकृत मेगा पार्क में कताई, बुनाई, रंगाई, प्रसंस्करण और कपड़ा विनिर्माण के लिए छपाई का काम एक ही जगह पर किया जाएगा। इससे माल ढुलाई का खर्च बचेगा और उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अभी तक 10 राज्यों ने अपने यहां पार्क स्थापित करने में रुचि दिखाई है। इनमें तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं।

सेमीकंडक्टर के लिए सरकार बनाएगी टास्क फोर्स

वाहनों-इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली चिप सेमीकंडक्टर की कमी पर निगरानी के लिए सरकार टास्क फोर्स का गठन करेगी। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि टास्क फोर्स देश में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन पर भी सुझाव देगी।